हिमालयाज बिरेफ्त ऑफ हर्बल प्लांट्स

189. **श्री सोम पाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1992 के "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" समाचार पत्र में "हिमालयाज बिरेफ्त ऑफ हर्बल प्लांटस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की तस्करी द्वारा सरकार को हो रही करोड़ों रूपये की हानि को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) सरकार ने यह समाचार-रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) जड़ी-बूटियों, जड़ों, छालों, बीजों, औषधीय पौधों आदि के एकत्रीकरण सहित वन संसाधनों का दोहन भारतीय वन अधिनियम, 1927/ राज्य वन अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। अवैध निष्कर्षण के मामलों पर वन अधिकारियों द्वारा अपराध की प्रकृति एवं परिमाण के अनुसार, कार्रवाई की जाती है, जिसमें माल को जब्त करना, जुर्माना तथा कारावास आदि शामिल है। वन सुरक्षा तंत्र को उन्नत संचार सुविधाओं और बेहतर गोली-बारूद सुविधाओं से मजबूत बनाया गया है। साइटस के परिशिष्ट–1 में शामिल दुर्लभ पौधों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। जंगलों से पेड़-पौधों की सामग्री के निर्यात पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय उप निदेशकों तथा सहायक निदेशकों के जरिए नजर रखी जाती है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जैसे कुछ अनुसंधान संगठन द्वारा कुछ औषधीय पौधों की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जिनसे सक्रिय सार-तत्वों की प्रतिशतता एवं मात्रा अधिक प्राप्त होगी। किसानों द्वारा इन्हें खेती के लिए अपनाया जा रहा है।

Harassment by Pakistan Navy to Indian Fishermen

190. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whethtr Government are aware of the hauling up of the Indian fishermen and terror created by the Pakistan marine security Agency in the Sea of the Kuchh coast by strawing beyond the limits following the Ayodhya incidents; and

(b) if so, what action has been taken by Government check the violation of Indian water by the Pakistan marine SecurityAgency besides ensuring safety of the Indian fishermen?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Government are aware of instances of harassment of Indian fishermen by Pakistani ships off the Coast of Gujarat from time to time as well as in the recent period.

(b) Government have taken up this matter with the Government of Pakistan through diplomatic channels. Regular and continuous petrolling of our waters by the coast Guard is also being maintained.

Bangladesh Nationals bid to cross the border

191. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bangladeshi Muslims had announced a plan of mass crossing of borders into India in December last to protest against the demolition of the Babri Masjid;

(b) if so, what steps were taken to thwart and prevent mass-violation of the borders;

(c) whether Government have lodged any protest with the Government of Bangladesh against their plan; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Some Islamic groups in Bangladesh announced on December 12, 1992 a plan to take a Long March to Ayodhya.

(b) Government viewing the above development with due concern, took up the matter appropriately with the Government of Bangladesh and, in addition, it took all other necessary measures to guard against the violation of our borders.

(c) and (d) Yes, Sir; a strong demarche was made to the Bangladesh High Commissioner in India on January 4, 1993, conveying our serious concern and strongly urging the Government of Bangladesh to stop the Long March. Further, our Spokesman stated on the same day that the proposed Long March was an unacceptable interference in our internal affairs. It was clearly the responsibility of the Government of Bangladesh to prevent any illegal border crossing by Bangladeshi nationals. He added that there was no question of permitting any violation of our territory and laws by foreign citizens. The Indian High Commissioner in Dhaka was asked to convey to the Government of Bangladesh that Government of India would take firm steps to prevent the border crossings. Consequently, the border crossing did not take place.

अयोध्या घटना पर बंगलादेश, पाकिस्तान और ईरान द्वारा दिए गए उत्तेजक बयान

192. **श्री गया सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश, पाकिस्तान और ईरान की सरकारें अयोध्या घटना के बाद से लगातार उत्तेजक बयान दे रही हैं, और

(ख) भारत सरकार सम्बन्धित सरकारों के साथ किस प्रकार इस मामले को उठा रही है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों ने अयोध्या घटना के बारे में कई आलोचनात्मक वक्तव्य दिए हैं। उनकी राष्ट्रीय असेम्बलियों में आलोचना करते हुए संकल्प पारित किए गए हैं। ईरान ने भी अपने आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए हैं।

(ख) सरकार ने राजनयिक सूत्रों के माध्यम से बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों के समक्ष अपना गहरा खेद व्यक्त किया है और उनके बयानों पर तीव्र निराशा व्यक्त की है जो कि हमारे आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप तो है ही, इसके साथ ही इसने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने का भी काम किया है। हमने अपने रूख से ईरान को भी अवगत करा दिया है।

Tenure of working for the Staff at regional Passport Office: Delhi

193. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether some tenure of working has been fixed for officers and staff of Regional Passport Office of Delhi;

(b) if so, what are the details thereof separately for each category of staff and officers;

(c) whether it is a fact that working of Passport office of Delhi is of routine nature which can be handled by any raw official with one to two weeks of practical working;